

छत्तीसगढ़ के राजनीति में उच्च शिक्षा एवं अनुदान

डॉ. सुस्मिता सेन

सहायक प्राध्यापक

राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रतिशत देश के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों से कम है, देश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य केरल, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब आदि हैं जो शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हैं।

प्रदेश में उच्च शिक्षा की यह स्थिति है कि यहां पर 1 मात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। जिसकी स्थिति देश के अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण कार्य की स्थिति में अपेक्षाकृत निम्न स्तर की है। प्रदेश में अन्य विश्वविद्यालयों की स्थिति यू.जी.सी. की रैंकिंग या गणना में अंतिम स्थिति में है, प्रदेश के विश्वविद्यालयों का शिक्षण कार्य देश के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में निम्न स्तर का है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों की स्थिति अति ही भयावह है। पिछले 06 दशकों में विश्वविद्यालयों से ऐसा कोई शोध नहीं निकला जिसने पूरे भारत या विश्व में प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान बनाई हो। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की गुणवत्ता में यह समस्या है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत विद्यार्थियों को रोजगार के लिये कड़ा संघर्ष करना पड़ता है।

वर्तमान में भारत में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की विषयों जो कला एवं वाणिज्य एवं विज्ञान से संबंधित हैं उनके विद्यार्थियों की स्थिति यह है कि 5 में से 4 विद्यार्थियों को रोजगार योग्य कौशल नहीं रखते हैं, एवं अन्य विषयों जैसे प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, यांत्रिकी एवं चिकित्सा के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की भी देश में यही स्थिति देखी जा सकती

है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कला, वाणिज्य, विज्ञान के विद्यार्थियों की स्थिति अत्यधिक सोचनीय है कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के स्नातक के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर जो शिक्षा प्रदान की जाती है जो की रोजगार परख नहीं होती है। प्रदेश के अन्य विषयों जैसे प्रौद्योगिकी, यांत्रिकी, चिकित्सा, प्रबंधन एवं विधि आदि के विद्यार्थियों की भी स्थिति यही है कि 10 में से एक विद्यार्थी को ही रोजगार प्राप्त होता है अन्य विद्यार्थियों की दशा अत्यधिक सोचनीय है उन्हें रोजगार अत्यधिक संघर्ष से प्राप्त होता या तो होता ही नहीं ।

प्रदेश की शिक्षा नीति एवं सरकार की उदासीनता मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उच्च शिक्षा को आरंभ से ही उपेक्षित समझा जाता रहा है। जबकि समाज की प्रगति विकास एवं उन्नयन के लिये उच्च शिक्षा का विशेष महत्व है । परन्तु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा विनियमन की व्यवस्था अनेक खामियों से भरी पड़ी है, उच्च शिक्षा अत्यधिक महंगी होने के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता एवं प्रवेश उपरांत भी उच्च शिक्षा का अध्ययन का स्तर या तो अत्यधिक उच्च होता है जिससे प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किये विद्यार्थियों की क्षमता से परे हों या तो इतना निम्न स्तर का होता है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने उपरांत कोई लाभ न दिला सके ।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना की अनुमति मिलने पर उच्च शिक्षण संस्थानों की निरन्तर वृद्धि हो रही है। किन्तु उच्च शिक्षण संस्थानों की वृद्धि से ही उच्च शिक्षा प्रतिशत में वृद्धि नहीं की जा सकती एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को देश के उच्च शिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेशों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता ।

छत्तीसगढ़ निर्माण के उपरांत देश के प्रौद्योगिकी, विधि एवं प्रबंधन उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा छत्तीसगढ़ में अपनी संस्था स्थापित करने पर छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल होने के लिये निरन्त्र प्रयासरत् हैं। किन्तु उच्च शिक्षण संस्थान होने से ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा नहीं दी जा सकती है छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा में त्रुटि, आर्थिक स्थिति एवं अन्य भी सामाजिक समस्याएं हैं जिनके कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते एवं

प्रदेश की उच्च शिक्षा की पद्धति भी अत्यधिक मंहगी एवं परम्परागत होने से उच्च शिक्षा की विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के केन्द्र स्थापित तो हुए हैं किन्तु उन उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शुल्क की अधिकता होने से उच्च शिक्षा ग्रहण करने में प्रदेश के विद्यार्थियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त शोध में प्रदेश में उच्च शिक्षा के संबंध में निम्न कठिनाईयों एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली की निम्न स्तर की शिक्षण कार्य को संक्षिप्त रूप से दर्शाया गया है। शोध का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रदेश की न केवल उच्च शिक्षा की प्रणाली की निम्न स्थिति को दर्शाते हुए शिक्षण प्रणाली में उन्नत हो रहे प्रदेश की व्याख्या संक्षिप्त रूप से करना है। प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की त्रुटि में सुधार होने पर प्रदेश के उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। निरन्तर उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं उच्च शिक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन एवं यू.जी.सी. द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदेश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की सूची में सम्मिलित होने के लिये ज्यादा समय नहीं लगेगा ।